जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 131 प्रभात उदयपुर, रविवार 16 मार्च, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राहुल गाँधी एक सप्ताह की ''मैडिटेशन यात्रा'' पर वियतनाम गये

राहुल को ''मैडिटेशन'' (ध्यान लगाने) की जरूरत इन दिनों कुछ ज्यादा ही नज़र आ रही है

- पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है, कि हालांकि, राहुल की व्यक्तिगत लोकप्रियता, ''एक्सैप्टबिलिटी'' (जनता में स्वीकार्यता) बढ़ी है, पर वे अभी राज्यों में फैली अन्तर कलह व खेमेबाजी को सुलझाने में सफल होते नज़र नहीं आ रहे हैं।
- बिहार में, उनकी मुख्य सहयोगी पार्टी उनसे काफी नाराज़ है, क्योंकि राहुल बिहार में कन्हैया कुमार व पप्पू यादव को पार्टी में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वे इन दोनों को नेतृत्व सौंपने को भी तैयार हैं और आर.जे.डी. उनके इस फैसले को पसन्द नहीं कर रही।
- इसी प्रकार, अभी तक पंजाब के मुतल्लिक यह निर्णय नहीं ले पाये हैं, कि दलित नेता चन्नी को नेता बनवायें या किसी जट सिख को नेतृत्व सौंपें। राहुल व प्रियंका की पसन्द, दलित नेता चन्नी बुरी तरह हारे थे चुनाव में, क्योंकि, जट सिखों ने दलित को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया था।
- अनिर्णय की स्थिति, गुजरात में भी है। पिछली बार राहुल अहमदाबाद में कह आये, कि, कांग्रेस का ही एक बड़ा खेमा, भाजपा का मददगार है, अतः इन गैर-वफादारों को पार्टी से निकाल देना चाहिए, उनकी संख्या चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो। पर, उनके इस साहसी भाषण के बाद अभी तक गुजरात की कांग्रेस पार्टी में इस निर्णय की क्रियान्विति के बारे में कोई भी हलचल नहीं दिख रही।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 मार्च। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष 11 मार्च से 18 मार्च तक वियतनाम में हैं और इधर संसद का सत्र चल रहा है।

वे कथित रुप से वियतनाम के आर्थिक मॉडल के अध्ययन के लिये वहाँ गये हैं। वहाँ का आर्थिक मॉडल मूलतः समाजवादी है, क्योंकि वियतनाम प्राथमिक रुप से एक कल्याणकारी देश है। लेकिन अन्दरुनी लोगों का कहना है कि वे वहाँ ध्यान करने के लिये गये हैं, क्योंकि वे ध्यान-प्रक्रिया से जुड़े हुये हैं तथा अपना काफी समय ध्यान में व्यतीत करते हैं।

जहाँ राहुल गांधी की स्वीकार्यता कुछ वर्गों में बढ़ रही है, लेकिन उनकी मुख्य समस्या यह है कि वे विभिन्न राज्यों और उनकी समस्याओं को ''हैंडल'' नहीं कर पाते हैं। और न उनके पास ऐसा कोई राजनैतिक सलाहकार है, जो उन्हें आधारभूत गलतियाँ करने से रोक सके।

राहुल गांधी के साथ लम्बे समय से यह समस्या बनी हुई है कि वे यह मानते हैं कि वे सबसे अच्छा स्वयं जानते हैं तथा उन्हें किसी सलाहकार की जरुरत नहीं है।

बिहार, जहाँ इस वर्ष के अन्त में चुनाव होने हैं, में राहुल गांधी बिहार की राजनीति में कन्हैया को उतार रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी, कन्हैया और पप्पू यादव को बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं, उससे बिहार में कांग्रेस का मित्र दल, आरजेडी अप्रसन्न है। राज्य कांग्रेस के नेताओं के गले भी यह बात नहीं उतर रही है। उनका कहना है कि इससे चुनावों में गठबंधन और कांग्रेस -दोनों को ही नुकसान होगा।

इसी कारण बिहार के कांग्रेस नेताओं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कम परीक्षा परिणाम देने पर प्रिंसिपल व व्याख्याता के खिलाफ हुई कार्रवाई रद्द

जयपुर, 15 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने विभागीय मापदंड से कम परीक्षा परिणाम देने पर प्रिंसिपल व व्याख्याता के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को, सही नहीं मानते हुए, रद्द कर दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश प्रिंसिपल महेन्द्र तिवाड़ी व व्याख्याता नेमीचंद की याचिकाओं पर दिया।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता 2019-2020 में कोटखावदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

- राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल महेन्द्र तिवाड़ी और व्याख्याता नेमीचंद की याचिका पर यह आदेश दिए। दोनों कोटखावदा के सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में पदस्थ थे।

राम नगर में प्रिंसिपल था। इस साल का सीनियर टीचर्स का गणित व इंग्लिश विषय का परीक्षा परिणाम विभागीय मापदंड से कम आया, जिस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने याचिकाकर्ता को चार्जशीट दी और जुलाई 2021 में उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि भी रोक दीं। इसकी अपील करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव ने दंड कम कर उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हम केन्द्र के शिक्षा बजट में हमारा शेयर देगें, पर हिन्दी का ''थोपना'' स्वीकार नहीं करेंगे'

तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने विधानसभा में 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो तमिलनाडु को केन्द्रीय शिक्षा बजट से मिलना था, पर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रोक दिया, क्योंकि तमिलनाडु ने नैशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी वित्त मंत्री के ''स्टैण्ड'' का पूरा समर्थन किया, और कहा, हम हमारे युवाओं को दो भाषा नीति से ही पढ़ायेंगे। क्योंकि तमिल व अंग्रेजी पढ़ाकर ही हमने उन्हें योग्य बनाया है, कि वे अपनी प्रतिभा व परिश्रम से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर छाये हुए हैं, तथा तमिल संस्कृति भी पूरी तरह सुरक्षित है।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 मार्च। तमिलनाडु तथा केन्द्र सरकार के बीच भाषा युद्ध और तेज हो गया है। तमिलनाडु ने अपने बजट लोगो में रुपये का प्रतीक हटाकर, तमिल अक्षर ''रु'' का प्रयोग किया है। तमिलनाडु के भाजपा नेतृत्व ने इस पर विरोध की बौछार शुरु कर दी है।

भाजपा की तमिल इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई तथा तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ भाजपा नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने द्रमुक तथा उसके नेता स्टालिन को फटकार लगाते हुये, कहा है कि वे भाषा विवाद को हास्यास्पद स्तर तक ले जा रहे हैं। इन दोनों भाजपा नेताओं ने तमिलनाडु सरकार के इस कदम को मूर्खतापूर्ण तथा उलटा असर करने वाला बताया है।

तमिलनाडु सरकार भारत के किसी भी राज्य की ऐसी पहली सरकार है, जिसने राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक को ड्रॉप किया है। प्रसंगवश बता दें कि इस प्रतीक को एक तमिल व्यक्ति ने ही डिज़ायन किया था। राज्य और केन्द्र सरकार के बीच खराब होते जा रहे सम्बंधों के बीच तमिलनाडु का यह कदम स्तब्ध करने वाला है।

इस मामले में तमिलनाडु का अगला कदम क्या होगा, यह प्रश्न लोगों के दिलो-दिमाग को परेशान कर रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी भौंहे टेढ़ी करते जा रहे हैं। केन्द्र इस बात पर अड़ा हुआ है कि राज्य को त्रिभाषा सूत्र की अनुपालना करनी ही होगी, और तमिलनाडु दशकों से इसका विरोध करता आ रहा है तथा द्विभाषा सूत्र को अपनाये हुये है।

इस समय अवरोध का मूल कारण यही है।

कल तमिलनाडु विधानसभा में पेश किये गये बजट में, राज्य के वित्त मंत्री थंगम तेनारासू ने 2000 करोड़ रु. का प्रावधान किया शिक्षा के मद में, किन्तु केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने तमिलनाडु को यह राशि दिये जाने से इसलिए इन्कार कर दिया, क्योंकि राज्य ने नैशनल एजुकेशन पॉलिसी स्वीकार नहीं की है।

बजट के लोगो में, रुपये के स्थान पर ''रु'' अंकित था, जो तमिल शब्द ''रूबई'' का प्रथम अक्षर है। यह अक्षर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुलिसकर्मियों ने नहीं खेली होली, अधिकारियों ने मनाया पर नहीं माने

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा, प्रदेश में होली शांति से सम्पन्न करवाने वाले खुद होली का बहिष्कार करने को मजबूर हैं

- पायलट ने कहा, मेरा सरकार से आग्रह है कि पुलिसकर्मियों की प्रमोशन, वेतन, भत्ते व अवकाश की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाए।
- प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिसकर्मियों की लंबित मांगे पूरी करने की मांग की।
- ज्ञातव्य है कि होली का त्यौहार शांति से सम्पन्न कराने के बाद होली के अगले दिन पुलिसकर्मी होली खेलते हैं पर इस बार पुलिसकर्मियों ने होली नहीं खेली, कर्मचारी संगठनों ने भी पुलिसकर्मियों का समर्थन किया।

जयपुर, 15 मार्च। अपनी लंबित मांगों का समाधान न होने से नाराज पुलिस कर्मियों ने होली नहीं खेली। अधिकारियों ने मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने होली खेलने से साफ इन्कार कर दिया। इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से पुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। इस मामले में सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित केबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग करते हुए लंबित मांगों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है।

सचिन पायलट ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि प्रदेशभर में होली संपन्न कराने में पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही है, लेकिन अब अपनी लंबित मांगों को लेकर वे खुद होली का बहिष्कार करने को मजबूर हैं। प्रमोशन, भत्ता बढ़ाने, अवकाश, स्थानांतरण पॉलिसी आदि को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। इन मुद्दों को लेकर आज राजस्थान के कई क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों ने होली मनाने से मना कर दिया है। पुलिसकर्मियों के हितों की मजबूती से पैरवी करते हुए सरकार से निवेदन है कि संवेदनशीलता से इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए।

पुलिसकर्मियों द्वारा होली बहिष्कार को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिखा है कि ''पुलिसकर्मियों द्वारा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जेडीसी, जेडीए सचिव व जोन उपायुक्त जमानती वारंट से तलब

जयपुर, 15 मार्च। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर जेडीसी आनंदी, जेडीए सचिव निशांत जैन व ज़ोन उपायुक्त राकेश मीना को दस-दस हज़ार रुपए के जमानती वारंट से 29 मार्च को तलब किया है। आयोग के अध्यक्ष

- जिला उपभोक्ता आयोग -द्वितीय ने अदालती आदेश का पालन नहीं होने पर जेडीसी आनंदी, जेडीए सचिव निशांत जैन व ज़ोन उपायुक्त राकेश मीणा का जमानती वारंट जारी किया।

ग्यारसीलाल मीना ने यह निर्देश नकुलेश्वर दत्त के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 29 अक्टूबर 2024 को उपभोक्ता आयोग ने जेडीए को निर्देश दिए थे कि वह एक महीने में भूखंड का कब्जा परिवादी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रूस बातचीत से पहले यूक्रेन का अधिकतम हिस्सा दबा लेना चाहता है

इसी रणनीति के तहत रूस कोई खास तत्परता नहीं दिखा रहा, समझौते की बातचीत के लिए सजाई गई टेबिल पर बैठने के लिए

- अमेरिका की टीम युद्ध विराम का समझौता तैयार करने के लिए मॉस्को पहुंच चुकी है। टीम का स्वागत करने जब पुतिन आये, तो पूरी तरह से सैनिक वर्दी में थे, तथा घूम-गूम कर अपने सेना के कमाण्डरों से बातचीत व हंसी मज़ाक कर रहे थे।
- अमेरिका की टीम जिस हवाई अड्डे पर उतरी है, वह यूक्रेन का हिस्सा था। अतः रूस का मकसद था, यह जताना कि युद्ध भूमि में स्थिति उसके नियंत्रण में है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की टीम के उच्चाधिकारी यूरी उषाकोव ने कहा, ''हम ने अमेरिका-यूक्रेन की सऊदी अरब में हुई वार्ता को गहराई से देखा व समझा है, यह और कुछ नहीं एक अस्थाई ''सीज़ फायर'' है, स्थाई समझौते के रूप में हमें कतई स्वीकार नहीं है।''

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 मार्च। जब यूक्रेन-रुस वार्ता के लिए गुरुवार को यू.एस प्रैसिडैंट के विशेष दूत मॉस्को पहुँचे तो रुस के राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति और हठधर्मिता का पूरा प्रदर्शन किया। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ गुरुवार को जब रुस के वनुकोवो हवाई अड्डे पर पहुँचे, उसी समय रुस के राष्ट्रपति ने कुर्स्क क्षेत्र और उसके सबसे बड़े शहर सुदझा का दौरा किया, जो पहले यूक्रेनियों के कब्जे में था।

पुतिन सैन्य वर्दी में थे और रुसी सैन्य कमाण्ड का दौरा करते हुए वो स्थानीय कमाण्ड प्रमुखों से मिले। उन्होंने रुसी श्रेष्ठता का एक मजबूत संदेश दिया और यूक्रेन की ओर से लड़ने वाले विदेशी मिलिशिया को कड़ी कार्यवाही और प्रतिशोध की चेतावनी दी।

पुतिन ने स्थानीय क्षेत्र में किए गए प्रदर्शनों में ताकत और निर्दयता की छवि पेश करने की कोशिश की। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य, यूक्रेन में रुस की उपस्थिति तथा रुसी सेना की अपराजेयता को किसी भी तरह के खतरे को चेतावनी देना था।

यह सब, आगामी वार्ताओं में सौदेबाजी के लिए किया गया था। अमेरिका, सऊदी अरेबिया में यूक्रेनियों के साथ बातचीत के बाद मॉस्को में बातचीत करने वाला है। कुछ शीर्ष अमेरिकी राजनयिक और रणनीतिकार रुसियों के साथ वार्ता करने के लिए मॉस्को आ रहे हैं।

जहाँ अमेरिका, अपने राष्ट्रपति के पहले के इन दावों को, कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में युद्ध कभी नहीं होता, या फिर वे युद्ध को जल्दी समाप्त करवा देंगे, सही साबित करने का जी तोड़ प्रयास कर रहा है, वहीं, रुस के शीर्ष राजनयिक इस संपूर्ण पहल पर पानी फेर रहे हैं।

रुसी राष्ट्रपति के सहायक, यूरी उशाकोव ने कहा, कि उन्होंने सउदी अरब में हुई अमरीकी -यूक्रेनी वार्ता और जो स्थिति बनी, उसके बारे में जानकारी ली थी। उन्होंने कहा कि संभावित आसान समझौता, ''यूक्रेनी मिलिटरी के लिए एक अस्थाई राहत'' से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का समझौता रुसियों को स्वीकार्य नहीं था।

अमरीकियों ने पहले कहा था कि यूक्रेन ने अमरीकी प्रस्तावों को स्वीकार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक दिन पहले ही विपश्यना शिविर छोड़ा केजरीवाल ने

होशियारपुर, 15 मार्च। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजब और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को होशियारपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर आनंदगढ़ गांव में धम्म धजा विपश्यना केंद्र (डीडीवीसी) में 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान सत्र पूरा करने से पहले ही रवाना हो गए।

- आप प्रवक्ता ने बताया कि केजरीवाल ने अपने मैडिटेशन टीचर से छुट्टी लेकर शिविर छोड़ा है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कल रात यहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचीं और आज सुबह डीडीवीसी गईं। इसके बाद केजरीवाल और उनकी पत्नी सड़क मार्ग से जालंधर के लिए रवाना हो गए।

उन्हें विदा करने के लिए सांसद डॉ. राज कुमार, पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह और विधायक ब्रह्म शंकर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जबरदस्ती व विरोध नहीं, दया व करूणा के पुल से दूरियां घटती हैं

कैडबरी डेयरी मिल्क ने विज्ञापन में नॉर्थ व साउथ के भाषा विवाद का नाज़ुक समाधान दिखाने की हिम्मत दिखाई, जबकि, बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ फेल हो गये

- विज्ञापन के शुरू होते ही एक साधारण रोज़मर्रा के दृष्टि से, गृहणियां आपस में बातचीत कर रही हैं हिन्दी में, तभी एक तमिल भाषी नई पड़ौसन बातचीत से जुड़ती है। एक गृहणी ने नई पड़ौसन की थोड़ी सी उलझन समझते हुए इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया, जिससे नई पड़ौसन भी बातचीत में शामिल हो जाये, यह एक छोटी सी संवेदनशील चेष्टा, कारगर साबित हुई, जबकि भाषा के विवाद ने देश को एक युद्ध भूमि बनाकर रख दिया है।
- कैडबरी के विज्ञापन ने देश की अन्तरआत्मा को झकझोर तो दिया, कुछ क्षणों के लिए। पर, यह केवल एक चतुर विज्ञापन ही है, जो सही समय पर आया और चर्चित हो गया।

-सुकुमार शाह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 मार्च। एक ऐसा देश है, जहां भाषा संवाद का जरिया होने से कहीं अधिक पहचान, संस्कृति का प्रतीक है और अब तो राजनैतिक निष्ठा का भी प्रतीक बन गई है, वहीं कैड्बरी डेयरी मिल्क का नया विज्ञापन तीखी बहस का मुद्दा बन गया है। इस समय जबकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भाषाई तनाव पनप रहा है, ऐसे में इस ब्रांड ने एक कोमल, किंतु सशक्त रूख अपनाया है। यह विज्ञापन कहता है, जोर-जबर्दस्ती या विरोध करने से नहीं, बल्कि ''प्रेम'' से मतभेद की खाई भरती है।

यह विज्ञापन ऑन लाइन काफी लोकप्रिय हो रहा है, इसमें रोजमर्रा का परिदृश्य दिखाया गया है, कुछ महिलाएं हिंदी में गपशप कर रही हैं कि तभी एक तमिल भाषी पड़ौसन उनके साथ शामिल हो जाती है। उनमें से एक महिला देखती है कि तमिल महिला भाषा समझ नहीं पाने से परेशान लग रही है तो वह अंग्रेजी में बोलती है, ताकि वह महिला भी खुद को गपशप का हिस्सा महसूस कर सके। यह एक छोटी सी कोशिश है, पर इसमें एक सामाजिक राजनैतिक संदेश है, वो भी ऐसे देश में, जहाँ भाषा अक्सर युद्ध का मैदान बन जाती है।

कई दशकों से भारतीय राजनीति में हिंदी भाषा थोपने का विवाद चल रह है। केन्द्र सरकार हिंदी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहती है, चाहे वह सरकारी काम हो या प्रतियोगी परीक्षाओं में या शिक्षा नीति में। पर तमिलनाडु व दक्षिण भारतीय राज्यों में इसका कड़ा विरोध किया जाता है, जहां क्षेत्रीय दल, खासकर द्रमुक इन प्रयासों को अपनी भाषा और सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। तमिलनाडु बार-बार नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के त्रिभाषा फॉर्मूला को ठुकरा रहा है और उसने साफ कर दिया है कि तमिलनाडु में हिंदी का स्वागत नहीं होगा।

इस बेहद संवेदनशील विषय पर एड बना कर कैड्बरी डेयरी मिल्क भी राजनैतिक विवाद में प्रवेश कर गई है, पर टकराव का रूख अपनाए बिना। नॉर्थ-साउथ में उसने किसी का भी पक्ष नहीं लिया है, उल्टे भाषाई सद्भाव को दर्शाया है। संदेश साफ है, किसी को अपनाना जबरन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह प्रेम और करुणा से किया जा सकता है।

एक ब्रांड जो लम्बे समय से रिश्तों की गर्माहट और सबको साथ लेकर चलने के रूख पर चलता है, उसका यह विज्ञापन उसकी कॉरपोरेट पहचान को दर्शाता है। लेकिन क्या यह बहुत सर्तकता से उठाया गया मार्केटिंग का कदम है या फिर भारत में भाषाई विवाद में द्वंद में पड़ने का प्रयास है, इस पर बहस जारी है।

इस विज्ञापन पर ऑन लाइन प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। कई दर्शकों ने इसकी तारीफ की और कहा कि यह सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है, वो भी स्वाभाविक तरीके से, ज़ोर जबर्दस्ती से नहीं। एक दर्शक ने कहा ''मैं दक्षिण-उत्तर भारतीय भाषा विवाद को नहीं जानता, पर मैं इस ग्रेट विज्ञापन को मानता हूं। डेयरी मिल्क हमेशा सही नस पकड़ता है।'' एक अन्य दर्शक ने इसकी तारीफ कर इसे खूबसूरत और प्रशंसनीय विज्ञापन बताया।

लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोगों ने परिदृश्य की व्यवहारिकता पर सवाल उठाया। एक यूज़र ने कटाक्ष किया ''तो मैं ओडिशा के किसी गांव में जाऊं तो वहां यह उम्मीद करूं कि मेरी सुविधा के लिए वो अंग्रेजी में बात करेंगे।'' एक अन्य ने कहा ''संस्कृत क्यों नहीं, यह देवताओं की भाषा है, इसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चारागाह भूमि से कब्जा नहीं हटा, जिला कलैक्टर रिकॉर्ड सहित तलब

जयपुर, 15 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं की चिड़ावा तहसील की चारागाह भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में जिला कलेक्टर,

- हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने चिडावा तहसील की चारागाह भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले 25 मार्च को जिला कलैक्टर सहित एसडीओ और तहसीलदार को तलब किया है।

एसडीओ और तहसीलदार को 25 मार्च को तलब किया है। अदालत ने अधिकारियों से मामले का संपूर्ण रिकॉर्ड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)